(c) **Subordinate Staff:**
1600-40-1640-50-1690-60-1930-70-2210-80-2450-90-2720-100-3020

एक लाख रुपए से अधिक का बकाया आयकर

4292. **श्री नागमणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1995 तक 75,000 से अधिक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये से अधिक का आयकर बकाया था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार आयकर प्राप्त नहीं कर पायी है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार किन्ही बकाया करों को वसूल नही कर पायी है। इसके बावजूद भी कि उपर्युक्त (अ) में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में कर की सही वसूली के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि कम्पनियों और गैर-कम्पनियों, दोनों के संबंध में बकाया कर की राशि जो 1.4.95 को 22, 698.64 करोड़ रु॰ थी, 31.3.96 को कम होकर 16,416.05 करोड़ रु॰ रह गयी थी और परिणामतः 27.7% की कमी हुई थी। किन्तु वर्ष के दौरान पूरे किये गये कर-निर्धारणों के कारण जारी की गई नई मांगों से यह कमी निष्फल हो गई है।

बकाया करों की वसूली करना एक समय लगने वाली और कठिन प्रक्रिया है। अधिकांश बकाया मांगे व्यापक रूप से विवादग्रस्त हैं और कर-निर्धारिती इनकी तब तक अदायगी न करने का प्रयास करते हैं जब तक कि वे उनको उपलब्ध सभी अपीलीय स्रोतों का उपयोग नहीं कर लेते हैं। अपीलों के विभिन्न स्तर होने के कारण अपीलों को अंतिम रूप देने में बहुत समय लगता है। अपीलों को अंतिम रूप दिए जाने तक, कर निर्धारिती न्यायालयों, समझौता आयोग, आयकर अपीलीय अधिकार और आयकर प्राधिकारियों से मांग की वसूली के लिए स्थगन प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते हैं।

Funds Allotted to Banks to Lend Money to Priority Sectors

4293. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government allotted more funds to public sector Banks to lend money to the priority sectors and also for industrial development of the country; and

(b) whether the Banks have achieved the target of financing private sector as per the directions of Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) Government of India have been providing recapitalisation support to nationalised banks to enable them to achieve the prescribed capital to risk- weighted assets ratio (CRAR) of 8 per cent. Banks are also required to invest this amount in capitalisation bonds issued by Government so that there is no cash outgo from the budget on this account. Increased capital base will enhance the capacity of banks to undertake more lending, including priority sector lendings.

(b) The outstanding amount of non-food bank credit of scheduled commercial banks stood at Rs. 268933 crore as on March 28, 1997 accounting for an increase of Rs. 24710 crore (10.1%) during the year 1996-97.

Loans under PMRY to the North - East Region

4294. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: